

IDBI बैंक के निजीकरण के खिलाफ बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन करें!

कामगार एकता कमिटी (KEC) का बयान, 22 अक्टूबर 2026

कामगार एकता कमिटी (KEC) IDBI बैंक के अधिकांश शेयर एक निजी वित्तीय संस्थान को बेचकर उसके निजीकरण के सरकारी फैसले की निंदा करती है।

KEC यूनाइटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयीज की मांगों को अपना पूरा समर्थन देती है। उनकी मांगें हैं कि IDBI बैंक का मालिकाना हक और नियंत्रण किसी और को न सौंपा जाए, और इसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में ही बनाए रखा जाए।

IDBI बैंक का निर्माण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के ज़रिए इकट्ठा किए गए सार्वजनिक धन से हुआ है। सार्वजनिक धन से बनाई गई संपत्तियों को निजी मुनाफ़े के लिए सौंप देना जन-विरोधी, समाज-विरोधी है।

2010-11 से 2019-20 के बीच, केंद्र सरकार ने IDBI बैंक में 27,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की पूंजी लगाई थी। जनवरी 2019 में IDBI बैंक में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने के बाद, LIC ने भी इसमें 26,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश किया। IDBI को एक मुनाफ़े वाला बैंक बनाने के लिए 53,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की पूंजी लगाने के बाद, अब सरकार अपनी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी सिर्फ 52,878 करोड़ रुपये में बेच रही है!

पहले हुए निजीकरणों की तरह, IDBI बैंक को भी कौड़ी के दाम पर बेचा जा रहा है। बोली लगाने वाले पूंजीपतियों के लिए इसे और आकर्षक बनाने के मकसद से, इसके न्यूनतम कीमत को लगभग 20% तक कम कर दिया गया। इसके अलावा, शेयर की कीमत में बैंक की सभी संपत्तियों का मूल्य शामिल नहीं है। ***IDBI बैंक के पास देश के सात सबसे बड़े शहरों में लगभग 120 संपत्तियां हैं।***

अकेले हैदराबाद में मौजूद इसकी एक संपत्ति की बाजार कीमत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

IDBI बैंक का निजीकरण बड़े भारतीय और विदेशी पूंजीपतियों के एजेंडे का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि जनता के पैसे और मजदूरों की मेहनत से बनाई गई संपत्तियों को निजी मुनाफे के लिए सौंप दिया जाए। पिछले पैंतीस वर्षों में सत्ता में आई हर पार्टी या गठबंधन ने इसी एजेंडे को आगे बढ़ाया है। 2021 में घोषित नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य "वित्तीय संस्थानों सहित केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की मौजूदगी को कम करना और निजी क्षेत्र के लिए निवेश के नए अवसर पैदा करना है"।

मजदूर वर्ग के लिए यह जरूरी है कि वह निजीकरण की हर कोशिश के खिलाफ एकजुट होकर एक समझौताहीन संघर्ष छेड़े। यह लड़ाई इस भावना के साथ लड़ी जानी चाहिए कि "एक पर हमला, सब पर हमला है!"

KEC सभी संगठनों के श्रमिकों से अपील करता है कि वे अपने सभी मतभेदों को भुलाकर, IDBI बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्थन में एकजुट हों, ताकि अब तक के सबसे बड़े निजीकरण के ज़रिए किए जा रहे इस जन-विरोधी और समाज-विरोधी हमले को रोका जा सके।

मजदूर एकता ज़िंदाबाद!

इंक्रलाब ज़िंदाबाद!

संपर्क: 9082420488, 9819323064; Visit www.aifap.org.in